

न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सीवर, आर०ए०एस०  
 राजस्व वाद संख्या : 283/2019 (80/2018)  
 GCMS NO. : 2018/00017

-: वादीगण :-

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. गिरधारीलाल पुत्र मोतीलाल
  2. नारायण पुत्र खंगार
  3. हेमाराम पुत्र नेतीराम
  4. भंवरलाल पुत्र लिखमाराम
  5. मंगलाराम पुत्र गणेशराम
  6. आसूराम पुत्र जोगाराम
  7. हुम्मराम पुत्र नारायणराम
  8. गैनाराम पुत्र प्रभूराम
  9. पुखराज पुत्र नन्दाराम
  10. चम्पा पत्नि पूनाराम
  11. कन्हैयालाल पुत्र लालूराम
  12. राजकीदेवी पत्नि पाबूराम
  13. मलाराम पुत्र पूनाराम
  14. अबाराम पुत्र रईगराम
  15. जीयाराम पुत्र रईगराम
  16. बगाराम पुत्र जसाराम
  17. ओगड़राम पुत्र रामाराम
  18. नाथूराम पुत्र ढगलाराम
  19. कालूराम पुत्र भीकाराम
  20. पन्नाराम पुत्र पेमाराम
- जातियान सिरवी निवासीगण  
 चावण्डिया तहसील जैतारण।

1. गुमानसिंह पुत्र जबरसिंह
2. नाराणसिंह पुत्र जबरसिंह
3. नवरतनसिंह पुत्र माधोसिंह
4. विजयसिंह पुत्र माधोसिंह  
जातियान राजपूत, निवासीगण  
चावण्डिया तहसील जैतारण।
5. तहसीलदार एवं उप पंजीयन  
अधिकारी जैतारण जिला पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.

तारीख रजू 25/09/2019

- उपस्थित:-
1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
  2. श्री करणीदान चरण, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

-: निर्णय :-

दिनांक:- 31/08/2021

वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. विरुद्ध अप्रार्थीगण/वादीगण इस आशय का बिन्दुवार प्रस्तुत किया कि वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के खातेदारी रास्ता किस्म गैर मुमकिन रास्ता के बारे में मुख्य अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी के रास्ते को सार्वजनिक रास्ता घोषित करने राजस्व अभिलेख में

सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)



सार्वजनिक रास्ता अंकन किये जाने का अनुतोष मांगा गया है एवं अनुषांगिक अनुतोष के रूप में स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुतोष मांगा गया है। वादीगण के दावे के सम्पूर्ण अभिवचनों के आधार पर प्रतिवादीगण के खातेदारी के रास्ते की भूमि में सड़क बना देने से सार्वजनिक रास्ते की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है तथा वादग्रस्त रास्ते से हमेशा से अपने गांव से कुओं पर आना जाना बताया गया है जिससे प्रतिवादीगण के कोई खातेदारी अधिकार शेष बचे नहीं रहना बताया गया। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि से अपने कुए पर बने मकानों में भी आने-जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता कदीमी से वादग्रस्त रास्ते का होना बताया गया व कुछ समय पूर्व वादग्रस्त रास्ते पर डामरीकरण कराया जाने से वादग्रस्त भूमि डामरीकृत सड़क के रूप में उपयोग लिया जाने के कथन अभिकथित किये गये तथा अनुतोष में वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक रास्ता निरन्तर घोषित किया जाने, व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खातेदारी हक से नाम विलोपित किये जाने कि प्रार्थना की गई व स्थाई निषेधाज्ञा भी चाही गई। वादीगण के सम्पूर्ण वादपत्र में वर्णित अभिवचन से अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट होता है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर सुखाधिकारों के अधिकार उत्पन्न होने के आधारों पर रास्ते बाबत् घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया है जो विशिष्ट रूप से अभिवचनों में अभिकथित नहीं किया गया यदि तर्क के रूप में सुखाधिकारों के आधार पर वादीगण के द्वारा अनुतोष चाहा गया तो उस स्थिति में सिविल न्यायालय को इस प्रकार का अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार होता है। राजस्व न्यायालय को इस प्रकार का अनुतोष प्रदान करने के लिए कोई श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार निहित नहीं होता है। साथ ही सुखाधिकारों की घोषणा में खातेदारी हक समाप्त नहीं होते हैं केवल मात्र सुखाधिकार तय होते हैं। विधि में वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक रास्ते के रूप में अंकन कराने बाबत् कोई प्रावधान नहीं है। वादीगण के वाद में न तो विधि के अभिव्यक्त प्रावधान विवादित प्रावधानों के बारे में कोई अभिवचन किये हैं केवल मात्र वेग, अस्पष्ट, सारहीन, अभिवचनों के आधार पर वादीगण किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है अर्थात् वादीगण के अभिवचनों के आधार पर वादीगण राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यदि तर्क में रूप में प्रतिफल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त किया जाता है वह भी वादीगण के अभिवचन नहीं है एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ऐसा अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वादीगण के अभिवचनों के अनुसार वादीगण प्रतिवादीगा संख्या 1,2 के संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि को उपयोग किया जाना प्रकट होता है जिससे प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त को कोई बल नहीं मिलता है ऐसी स्थिति में वादीगण के द्वारा उक्त वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है जिससे वादीगण का वाद इसी स्तर निरस्त होने योग्य है। वादीगण के वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचनों में सार्वजनिक रास्ते की घोषणा बाबत् अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किसी अभिव्यक्त निरन्तर कब्जे या विवक्षित विधिक प्रावधानों के तहत कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। राजस्थान काश्कारी अधिनियम की धारा 251(क) में ही केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी को

क्षेत्राधिकार प्राप्त है लेकिन वादीगण के वादपत्र में धारा 251(क) के संदर्भ में कोई अभिवचन नहीं किये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उक्त धारा के अलावा रास्ते के संदर्भ में न्यायालय आप को कोई श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार अभिप्रेत नहीं है। जिससे भी वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद, वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से न्यायालय आपको श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार नहीं होने, विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा जवाब पेश किया गया, जो सा.मि. है। अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक का जबाब है कि प्रतिवादीगण के नाम जो खसरा नम्बर 157 व 158 इन्द्राज है उसके सम्बन्ध में नाम हटाने की घोषणा का वादपत्र वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या दो का जबाब है कि वादीगण द्वारा जो गलत नाम प्रतिवादीगण का इन्द्राज हो गया उसे हटाकर खसरा नम्बर 157 व 158 को सावर्जनिक रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या तीन का जबाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य सही है कि वादीगण की जो इस्तदुआ है वह वादग्रस्त खसरा नम्बर में प्रतिवादीगण का नाम हटाने की है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या चार का जबाब है कि वादपत्र में दर्ज अभिकथनों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादपत्र राजस्व न्यायालय में विचारणीय की क्षेत्राधिकारिकता रखता तथा न कि सिविल न्यायालय की। क्योंकि वादीगण ने सुखाचार अधिकार नहीं चाहा है। बल्कि प्रतिवादीगण का जो गलत नाम रास्ते की भूमि में इन्द्राज हो गया उसे जरिये घोषणात्मक हटाने की इस्तदुआ चाही है और ऐसी इस्तदुआ मात्र राजस्व न्यायालय में वादपत्र कर प्राप्त की जा सकती है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या पांच का जबाब है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सही अभिवचनों पर आधारित है कोई तथ्य नहीं छुपाये गये है और कानून के अनुसार वादपत्र प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या छह का जबाब है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में लिखित अभिवचनों से स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण ने जो अनुतोष चाहा है वह राजस्व न्यायालय से ही प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का किसी आराजी में गलत नाम इन्द्राज हो जाता है तो उस आराजी से नाम हटाने या जोड़ने या दुरुस्ती करने का आदि का वादपत्र सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या सात का जबाब है कि वादपत्र को सम्पूर्ण पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण ने जो वादपत्र पेश किया उसमें स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का रास्ते की जमीन में नाम अंकित है जो गलत है क्योंकि खसरा नम्बर 157, 158 मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रहे हैं इसलिए गलत नाम इन्द्राज हो जाने की वजह से प्रतिवादीगण वादीगण को रास्ते की भूमि के उपयोग उपभोग बाबत बाधा अडचन पैदा करते हैं इसलिए वादीगण का वादपत्र तथाकथित गलत नाम इन्द्राज हो दुरुस्त करवाने का है इसलिए इस वादपत्र की सुनवाई की क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व


सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

न्यायालय को है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सारहीन है क्योंकि उक्त वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को होने से प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये-

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (शेखावत लॉ हाउस जोधपुर, 2012 एडिशन) पेज-145 (धारा 251 एवं 251ए), तृतीय अनुसूची पेज-180
2. 2009(3) वोल्जूम 57 C.C.C. पेज-720
3. 2015(1) वोल्जूम 80 C.C.C. पेज-351
4. 2000(1) वोल्जूम 25 C.C.C. पेज-225
5. 2017(1) D.N.J. पेज-1
6. 2015(1) रिविजन D.N.J. पेज-221
7. भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1822 द्विभाषी संस्करण (कानून प्रकाशक, 2009 एडिशन)

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पत्रावली मय वाद-पत्र एवं संगत विधिके प्रावधानों यथा धारा 207 रा.का.अधि., तृतीय अनुसूची, रा.का.अधि., 1955 का अध्ययन किया। वाद-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी किस्म गै.मु. रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित करवाने हेतु वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया है। प्रथम तो रास्ते के किसी भी प्रकार के विवाद के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में केवल 2 ही धाराओं में प्रावधान दिये गये हैं यथा 251 एवं 251'क'। उक्त दोनों धाराओं के अधीन कार्यवाही न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने यह कथन किया है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर सुखाधिकारों के अधिकार उत्पन्न होने के आधारों पर रास्ते बाबत् घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया है एवं न्यायालय हाजा को इस प्रकार के अनुतोष प्रदान करने के लिए कोई श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार विहित नहीं होता है। वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने वाद-पत्र व जवाब प्रा.पत्र में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण वादीगण को रास्ते की भूमि के उपयोग/उपभोग बाबत् बाधा/अडचन पैदा करते हैं। अतः वादीगण/अप्रार्थी एवं प्रार्थी/प्रतिवादीगण के कथनों से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा रास्ते की भूमि के उपयोग/उपभोग में बाधा/अडचन होने पर अपने सुखाधिकारों के अधिकार के संरक्षण हेतु वादग्रस्त आराजी को सार्वजनिक रास्ता घोषित करवाने बाबत् अनुतोष चाहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 एवं अनुसूची-तृतीय में धारा 88 के


  
 सहायक कुलकर्  
 (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अन्तर्गत केवल खातेदारी अधिकारों की ही घोषणा की जा सकती है, न कि सार्वजनिक रास्ते की। अतः उक्त अनुतोष न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं है। वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि उक्त अनुतोष राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है परन्तु उक्त कथन के समर्थन में वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के किन विधिक प्रावधानों के तहत है इसका उल्लेख नहीं किया गया है व इससे सम्बन्धित न ही कोई न्यायिक नजीरों ही प्रस्तुत की है जिससे की अप्रार्थी/वादीगण के कथन साबित होते हो। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207, अनुसूची- तृतीय से बाधित है। वादीगण संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुतोष प्राप्त करने के लिए इस्तदुआ करने के लिए स्वतन्त्र है, अतः हम प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद पत्र को इसी स्तर पर खारिज करना विधि सम्मत समझते है।


**-:: आदेश:-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वाद-पत्र वादीगण न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से परे होने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207, अनुसूची-तृतीय से बाधित होने से नामंजूर किया जाता है। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) जैतारण  
(फैसल न्यायालय (राज०))

निर्णय आज दिनांक 31/08/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) जैतारण  
(फैसल न्यायालय (पाली))  
जिला-पाली (राज०)

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अधिकारी, जैतारण  
बईजलास :- श्रीमति मधुलिका सीवर, आर0ए0एस0

-: वादीगण :-

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. गिरधारीलाल पुत्र मोतीलाल
2. नारायण पुत्र खंगार
3. हेमाराम पुत्र नेतीराम
4. भंवरलाल पुत्र लिखमाराम
5. मंगलाराम पुत्र गणेशराम
6. आसूराम पुत्र जोगाराम
7. हुक्माराम पुत्र नारायणराम
8. गैनाराम पुत्र प्रभूराम
9. पुखराज पुत्र नन्दाराम
10. चम्पा पत्नि पूनाराम
11. कन्हैयालाल पुत्र लालूराम
12. राजकीदेवी पत्नि पाबूराम
13. मलाराम पुत्र पूनाराम
14. अबाराम पुत्र रईगराम
15. जीयाराम पुत्र रईगराम
16. बगाराम पुत्र जसाराम
17. ओगड़राम पुत्र रामाराम
18. नाथूराम पुत्र ढगलाराम
19. कालूराम पुत्र भीकाराम
20. पन्नाराम पुत्र पेमाराम

1. गुमानसिंह पुत्र जबरसिंह
2. नाराणसिंह पुत्र जबरसिंह
3. नवरतनसिंह पुत्र माधोसिंह
4. विजयसिंह पुत्र माधोसिंह  
जातियान राजपूत, निवासीगण  
चावण्डिया तहसील जैतारण।
5. तहसीलदार एवं उप पंजीयन  
अधिकारी जैतारण जिला पाली।

जातियान सिरवी निवासीगण  
चावण्डिया तहसील जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई  
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 283/2019 (80/2018)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री करणीदान चारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी को सार्वजनिक रास्ता घोषित करवाने बाबत् अनुतोष चाहा है। अतः वाद-पत्र वादी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से परे होंगे एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207, अनुसूची-तृतीय से बाधित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण अंतर्गत आदेश-07, नियम-11 सी. पी.सी. बखूबी साबित होंगे से स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....  
 -.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।  
 बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/08/2021 को  
 जारी किया गया ।

मोहर



सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रैक), जैतारण (पाली)  
 जिला-पाली (राज 0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	-	२.००	स्टाम्प वकालतनामा	-	३.००
स्टाम्प वकालतनामा	-	२.००	स्टाम्प अर्जी	-	२.००
स्टाम्प वजह सबूत	-	०.००	महनताना वकील	-	०
महनताना वकील	-	०.००	खर्चा गवाहान	-	०
खर्चा गवाहान	-	३.००	फीस कमीश्नर	-	०
फीस कमीश्नर	-	०	बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	०
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	०	मुत्फरिक	-	०
मिजान:-	७.००		मिजान:-	५.००	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्की के जरिए  
 दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।